An amount of about Rs. 154 crores was released to the State Government in respect of these schemes during 1992-93, 1993-94 and 1994-95. In addition, an amount of Rs. 115 crores was released to the State Government during 1992-93 and 1993-94 for concessional sale of decontrolled fertilizers to farmers. The implementation of the schemes has helped in substantial increase in production of foodgrains and oilseeds over the production in 1991-92.

(d) and (e) To boost agricultural/horticultural production in the State, incentives are being provided to resource poor farmers for the use of critical inputs like seeds/planting material, farm implements, seed minikits, etc. Demonstrations and farmers' training are also organised on production technology, Integrated Pest Management, etc. Assistance is also provided to farmers for area expansion and drip installation, mulching and polygreen houses under horticulture programmes. These measures will be continued during the Eighth Plan period.

Uniformity in the Prices of Fruits and Vegetables

7443. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is uniformity in the prices of fruits and vegetables being sold by the outlets of Mother Dairy in Delhi;

(b) if not the reasons therefor; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to remove the difference in prices?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

(b) The variation is mainly to avoid problems of under-pricing/over-pricing in relation to the open market where the prices vary from lacality to locality.

(c) Not necessary in view of above.

दलहनों के उत्पादन का लक्ष्य

7444. **प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान दलहनों के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शुष्क क्षेत्रों में लघु और सीमान्त कृषकों को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई व्यावहारिक योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) वर्ष 1994-95 के लिए दलहनों के लिए निर्धारित लक्ष्य 15.5 मिलियन मीटरी टन था।

(ख) तथा (ग) दलहन मूलतः वर्षा सिंचित फसलें है। इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी राज्यों में 223 जिलों को कवर करते हुए एक केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत, लघु तथा सीमान्त किसानों सहित सभी श्रेणी के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता विभिन्न घटकों जैसे बीजों के उत्पादन और वितरण, उन्नत फार्म उपकरणों, छिड़काव सैटों, एकीकृत कीट प्रबन्धन, दाल प्रोसेसरों, भण्डारण धानियों, सूक्ष्म-पोषकतत्वों, राइजोबियम कल्चर आदि के लिए दी जाती है।

दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

7445. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है देश में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की दर में निरन्तर कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले कुछ दशकों के आंकड़े एकत्र किये हैं तथा दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में निरंतर कमी के क्या कारण थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत दशकों में दालों के प्रति हैक्टेयर उत्पादन में कोई संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश दालों के उत्पादन के लिए केवल 30 प्रतिशत परिष्कृत बीज

उपलब्ध हैं और देश में दालों के परिष्कृत बीज आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अरविंद नेताम): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। दोनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, जनसंख्या में वृद्धि की तुलना में दलहनों के उत्पादन की धीमी गति से वृद्धि के कारण हुई है।

(ग) पिछले दशक में देश में दलहनों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि की गति धीमी रही है।

(घ) दालों में वर्तमान बीज प्रतिस्थापन दर कम है। दालों के बीज की कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत बीज ग्रांव योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम जैसी बीज उत्पादन एजेंसियों को भी प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है।

आनुवांशिक इंजीनियरिंग को बढ़ावा देना

7446. श्री अजीत जोगी:
श्री मूलचन्द मीणा:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पौधों को अधिक लचीला बनाने के लिए देश में आनुवांशिक इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है / किये जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस॰ कृष्ण कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आनुवंशिक तौर पर पौधों के विकास के लिए जो कीट-व्याधियों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने वाले जैविक दबाओं तथा सूखा एवं मृदा लवणता जैसे अजैविक दबाओं को सह सकें, भा॰कृ॰अ॰परिषद (आई॰सी॰ए॰आर॰) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अनुसंधान संबंधी अनेक कार्य शुरू किए हैं। कपास, तम्बाकू चना, सरसों और चावल जैसी फसलों के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। तम्बाकू सरसों और चना में कीट-प्रतिरोधी जीनों का पहले ही समावेश किया जा चुका है। अब जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान भा॰कृ॰अ॰ के सभी फसल अनुसंधान संस्थानों का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसके अतिरिक्त भा॰कृ॰अ॰ संस्थान, नई दिल्ली में पौध विज्ञान में जैव-प्रौद्योगिकी और आनुवंशिक इंजीनियरी में अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने पौध मोलेकूलर बायोलाजी के लिए केन्द्र की स्थापना हेतु भा॰कृ॰अ॰प॰ के संस्थानों एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Self- Sufficiency of Indian Drug Industry

7447. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian drug Industry is 99% selfsufficient in formulations and 70% in bulk drugs with its exports totalling about Rs. 1400 crore;

(b) whether it is also a fact that the present Indian Patents Act 1970 is capable of meting the needs of drugs and medicines for the poor;

(c) whether it is also a fact that the present rate of drugs are just; and

(d) if so, how far the availability of essential as well as non-essential drugs at prices afforadable by the poor will be ensured after the present amendment in the Act of 1970 comes into operation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILEZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) The Indian drug industry is producing almost complete range of formulations needed in the country and also meets about 70% of bulk drug requirement. Trade balance has been favourable for the last four years and during 1993-94, exports were of the order of Rs. 1781.40 crores.

(b) to (d) Availability of medicines is dependent upon a variety of factors viz.